VANI
Celebrating 30 Years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

जी 20 प्रेसीडेंसी (अध्यक्षता) एजेंडा में भारतीय समाज सेवी क्षेत्र की प्रमुख मांगों पर नीति पत्र

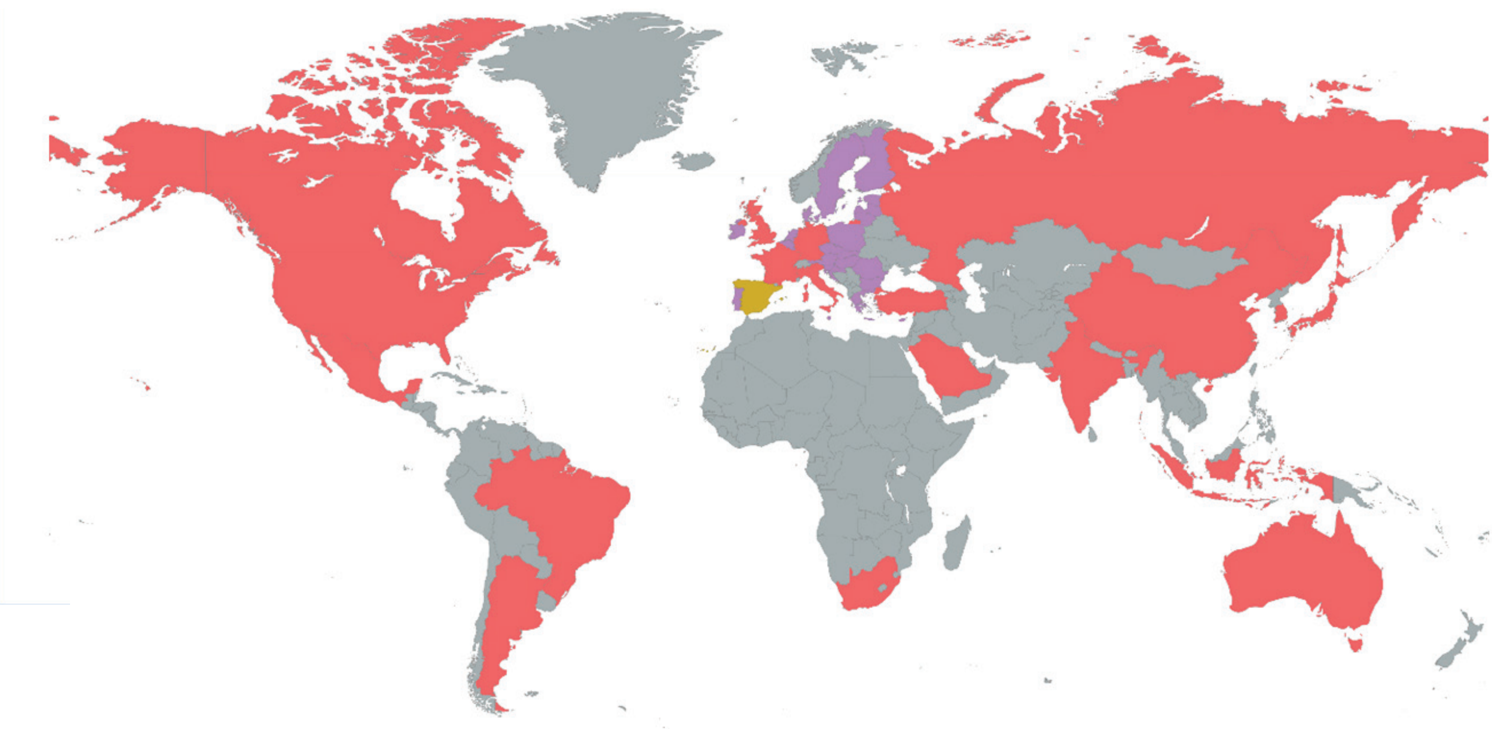

HEINRICH BÖLL STIFTUNG
INDIA

जी 20 प्रेसीडेंसी (अध्यक्षता) एजेंडा में भारतीय समाज सेवी क्षेत्र की प्रमुख मांगों पर नीति पत्र

लेखकः वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)

सितंबर 2022

कॉपीराइट (सी) वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
इस पुस्तक की सामग्री को प्रकाशक की उचित स्वीकृति के साथ पूर्ण या आंशिक रूप से पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रकाशन:
वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) वाणी हाउस, 7,
पीएसपी पॉकेट, सेक्टर -8, द्वारका, नई दिल्ली 110 077
फ़ोन: 91- 11 - 49148610, 40391661, 40391663
ई-मेल: info@vaniindia.org
वेबसाइट: www.vaniindia.org

@TeamVANI

@vani_info

@VANI India

@VANI Perspective

डिज़ाइन : शेड्स

जी 20 प्रेसीडेंसी (अध्यक्षता) एजेंडा में भारतीय समाज सेवी क्षेत्र की प्रमुख मांगों पर नीति पत्र

विषय-सूची

2023 में भारत की जी-20 अध्यक्षता 7

पृष्ठभूमि 8

भारत के लिए जी-20 का महत्व 9

भारत की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ 11

भारतीय प्रेसीडेंसी एजेंडा के प्रति समाज सेवी क्षेत्र का दृष्टिकोण 13

निष्कर्ष 21

संदर्भ 22

लघु रूप

जी 20- ग्रुप ऑफ़ 20

एसडीजी - सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स

सीएसओ - सिविल सोसाइटी आर्गेनाइजेशन

यूएई - यूनाइटेड अरब एमिरेट्स

ब्रिक्स - ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका

आईएमएफ - इंटरनेशनल मॉनेटरी फण्ड

डब्ल्यूटीओ - वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन

डब्ल्यूएचओ - वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन

आईबीएसए - इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका

जीडीपी - ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट

एनसीएसपीए - दी नेशनल कोलिशन फॉर स्ट्रेंग्थेनिंग एससी एंड एसटी (पीओए) एक्ट

एनसीआरबी- नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो

एससी- शेडूल कास्ट

सी20- सिविल 20

यूएचसी- यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज

एनईपी - नेशनल एजुकेशन पॉलिसी

एसएमएसए - समग्र शिक्षा अभियान

बीई- बजट एस्टीमेट

आरई- रिवाइज्ड एस्टीमेट

आईपीसीसी- इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज

एमएचए - मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स

एफसीआरए - फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट

जीएचजी - ग्रीनहाउस गैस एमिशन

2023 में भारत की जी-20 अध्यक्षता

जी-20 विकसित और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं सहित वैश्विक आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। जी-20 का कोई निश्चित सचिवालय नहीं है। प्रत्येक वर्ष, जी20 अध्यक्षता सदस्य देशों के बीच बदलती रहती है और आयोजक देश में सचिवालय की नियुक्ति की जाती है। 2023 में, पिछला आयोजन इंडोनेशिया द्वारा सम्पूर्ण किये जाने के बाद, भारत जी 20 अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेगा। यह पहली बार होगा, जब भारत जी20 की मेजबानी करेगा। जी 20 एजेंडा तय किया जाएगा, नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, साल भर में सरकार और समाज सेवी क्षेत्र सहित कई मंत्रिस्तरीय बैठकें होंगी।

सदस्यों को अधिकतम प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर नीतिगत निर्णयों का समन्वय करने में सक्षम बनाने के लिए जी20 का नेतृत्व करने के लिए कई तरह के प्रयास, विचार-विमर्श और गतिविधियां शामिल की जाएँगी। भारत सहित ग्लोबल साउथ का बढ़ता प्रभाव, सत्ता में बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को नियंत्रित करने तथा बहुपक्षवाद को मजबूत करने को दर्शाता है। भारत ने अपनी मानव संपत्ति और उद्यमशीलता पर ध्यान देने के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक होनहार राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इसलिए, भारत ने वैश्विक प्रशासन और जी 20 मंच में सक्रिय भागीदारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

स्थापना के बाद से, भारत शेरपा और वित्त ट्रैक दोनों में जी 20 का एक सक्रिय सदस्य रहा है। समावेशी विकास, दक्षिण-दक्षिण और उत्तर-दक्षिण सहयोग, एसडीजी और वित्तीय स्थिरता में इसका महत्वपूर्ण योगदान राष्ट्रीय एजेंडा के साथ-साथ वैश्विक प्राथमिकताओं के अनुरूप है। नेतृत्व का यह अवसर ऐसे समय में आया है, जब दुनिया संक्रमण के दौर से गुजर रही है। जबकि महामारी का प्रभाव कम हो रहा है, क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहे हैं। यह यूक्रेन-रूस युद्ध और भारत-चीन सीमा विवाद द्वारा अच्छी तरह से चित्रित किया जा सकता है।

पृष्ठभूमि

जी 20 में दुनिया की 19 विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, यानी अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैक्सिको, तुर्की, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इटली , फ्रांस, रूस, यूरोपीय संघ आदि। जी 20 में वैश्विक आबादी का लगभग दो-तिहाई और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% हिस्सा है। जी 20 को शुरू में केवल सात सदस्य देशों के साथ स्थापित किया गया था, जी 7 का प्रतिनिधित्व करते हुए, वित्तीय संकट को दूर करने के लिए, जिससे दुनिया 1997-1998 में गुजरी थी। आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के नियमन पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर प्रतिवर्ष मिलते थे। प्रगतिशील रूप से, मंच ने उन प्रमुख विकास समस्याओं पर चर्चा करना शुरू कर दिया जिनका सामना दुनिया कर रही है और उनसे निपटने के लिए संभावित समाधान प्रदान करता है। हर साल, जी 20 की अध्यक्षता में परिवर्तन के रूप में, एक नया और संशोधित एजेंडा तैयार किया जाता है, जो सहयोग के लिए प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दर्शाता है।

इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार-विमर्श करने के लिए, जी-20 दो भागो के माध्यम से कार्य करता है, अर्थात् वित्तीय और शेरपा । वित्तीय भाग, जी-20 के सभी सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा विनियमित और शासित होता है और विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्त और वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों से निपटता है। इस बीच, शेरपा भाग, वित्त के अलावा अन्य मुद्दों और जी-20 की प्रक्रियाओं और सुझावों के दस्तावेजीकरण के बारे में चर्चा करता है, जिसे अंतिम शिखर सम्मेलन में साझा किया जाता है। चूंकि शेरपा मूल रूप से मेजबान देश में जी20 की पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और निरिक्षण करने के लिए जिम्मेदार होता है, वह सरकार/उच्च अधिकारियों द्वारा निर्वाचित होता है, और सभी उच्च-स्तरीय बैठकों और संचार का हिस्सा है।

चूँकि जी 20 की अध्यक्षता हर साल बदलती है और समूह के किसी अन्य सदस्य द्वारा ली जाती है, इसलिए हर साल 'ट्रोइका', जिसमें जी 20 के पिछले वर्तमान और अगले अध्यक्ष शामिल होते हैं, पिछले वर्ष की तुलना में एजेंडा में निरंतरता

बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते है, और सभी सदस्य देशों से सम्बंधित एजेंडा सुनिश्चित करते है।

भारत के लिए जी-20 का महत्व

आश्चर्यजनक रूप से समय बड़ी तेजी से बीत रहा है। भारत दो महीने से भी कम समय में नवंबर 2022 में जी20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। यह पहली बार होगा जब भारत जी20 की मेजबानी करेगा। वर्ष भर चलने वाली यह अध्यक्षता नवंबर 2023 में ब्राजील को सौंप दी जाएगी, जिसका समापन अंतिम जी-20 शिखर सम्मेलन के साथ होगा। बड़ी संख्या में मंत्रियों, उच्च अधिकारियों, राजनयिकों, उद्यमियों, सीएसओ, कार्यकारी समूहों और संलग्न समूहों के साथ 200 से अधिक बैठकों की एक श्रृंखला के बाद, भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

सम्पूर्ण भारत में बैठकें होंगी और इसके दिसंबर 2022 से शुरू होने की योजना है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरीशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात जैसी कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित करने की भारत की योजना है।

पूर्व में भी, भारत ने कई बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों और सम्मेलनों की मेजबानी की है, जैसे कि 2015 में तीसरा भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन और 2016 में सिविल ब्रिक्स आदि। फिर भी, जी-20 जैसे आयोजन की मेजबानी करना बड़े ही गौरव की बात है। यह दुनिया भर के सभी आर्थिक एजेंडो के लिए एक संचालन समिति के रूप में कार्य करेगा। यह विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित निर्णयों को आकार देने और जी-20 राष्ट्रों को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों के लिए निश्चित रूप से जिम्मेदार होगा और इसमें अनुसंधान, चर्चा, विचार-विमर्श और शिखर सम्मेलन की साल भर की लंबी प्रक्रिया शामिल है जो वर्ष के अंत में एकल दस्तावेज़ के रूप में संगठित की जाती है।

हालाँकि, यह आवश्यक है कि भारत नीति निर्धारण प्रक्रिया में समूह के महत्व को घटाए या बढ़ाये बिना जी 20 मंच की गरिमा बनाए रखे। इस मंच का प्रभाव राजनीतिक और आर्थिक विषयो पर अप्रत्यक्ष भार वहन करता है। तथ्य यह है कि विश्व बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संगठन, जी20 मंच से जुड़े हुए हैं, जो इसे अपने आप में अत्यधिक प्रभावशाली बनाता है।
वित्तीय चुनौतियों का समाधान करना और उनकी पुनर्स्थापना के लिए संभावित

समाधान प्रदान करना जी20 की एक बड़ी उपलब्धि रही है। इस मंच का पहला दशक काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। हालाँकि, प्रमुख शक्तियों के बीच सभी भू-राजनीतिक विवादों में जी-20 का उत्तरार्द्ध मंच के लिए अपनी योग्यता साबित करने और प्रासंगिक बने रहने के लिए काफी चुनौती भरा रहा है। परिणामस्वरूप, ऐसे मोड़ पर जी-20 का नेतृत्व करना भारत के लिए एक बोझिल कार्य होगा।

जी-20 भू-अर्थशास्त्र भू-राजनीति से अत्यधिक प्रभावित हो रहा है। यूक्रेन-रूस युद्ध, भारत-चीन तनाव, अमेरिका और रूस के बीच दरार तथा अमेरिका और चीन के बीच शक्ति युद्ध, ये सभी इस बिंदु पर आकर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हावी हो रहे हैं। इसलिए भारतीय सचिवालय को सावधानीपूर्वक अपनी रणनीति बनाने और अभी से शुरुआत करने की आवश्यकता है। उन पर पूरी दुनिया के सामने बहुपक्षीय मंच की प्रतिष्ठा की रक्षा करने की भारी जिम्मेदारी है।

हालाँकि, जी-20 भारत को अपने लिए ब्रांडिंग और अपनी अभिनव उपलब्धियों और मील पत्थर को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है। विश्व स्तर पर, कोविड -19 का मुकाबला करने के लिए, अपने टीके और चिकित्सा सहायता के साथ, भारत की प्रभावी रणनीति हाल के दिनों में प्रमुख उपलब्धियों में से एक थी। इसके अलावा, भारत ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने, समय के साथ ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर स्विच करने, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने, घरेलू विनिर्माण के संबंध में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और देश में उद्यमिता का एक नया चेहरा स्थापित करने में कुछ पथप्रदर्शक कार्य किए हैं। चूंकि, दुनिया भर की सभी विकास समस्याओं से निपटने के लिए एक वर्ष पर्याप्त नहीं है, भारत निश्चित रूप से इस समय का उपयोग अपनी उपलब्धियों और उनकी प्रक्रियाओं को बाजार में लाने के लिए कर सकता है, ताकि अन्य देश इसे अपना सकें। जिस प्रकार भारत में राष्ट्रमंडल खेलों के समय बड़े पैमाने पर संरचना परिवर्तन हुआ था, उसी प्रकार वह फिर से इस अवसर का उपयोग देश में संरचना परिवर्तन के लिए कर सकता है, खासकर तब जब जी-20 मंच के तहत बैठकें कई स्थानों पर आयोजित की जाएंगी।

इसके अतिरिक्त, ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि, चार उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं आने वाले वर्षों में एक के बाद एक लगातार जी-20 की मेजबानी करेंगी - इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। यह विकासशील देशों के लिए कम शक्तिशाली लोकतंत्रों की प्राथमिकताओं के प्रति एकजुटता और प्रतिबद्धता दिखाने का एक अद्भुत अवसर है। इससे उन्हें दक्षिणी देशों के रुख को मजबूत करने का मौका मिलता है।

वास्तव में, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, जिन्हें एक साथ इब्सा (आईबीएसए) कहा जाता है, इस अवसर का उपयोग वैश्विक दक्षिण हितो पर आधारित एक

रणनीति विकसित करने के लिए कर सकते हैं, जो वे ब्रिक्स में करने में असमर्थ रहे हैं, चीन और रूस की भागीदारी के कारण । जी-20 अध्यक्षता की मेजबानी करते हुए वे अपनी साझेदारी को फिर से मजबूत कर सकते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के एक शानदार मंच का मेजबान होने के नाते, जी-20 एजेंडे के व्यापक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने और पूरी प्रक्रिया को समावेशी बनाने की जिम्मेदारी भारत को दी गई है। भारत को इस मंच के सभी सदस्यों के हितों की देखभाल करने में सक्षम होना होगा, जिसमें वे राष्ट्र भी शामिल हैं जिनका अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है।

उपरोक्त अवसरों के साथ तालमेल बिठाकर भारत एक व्यापक जी20 रणनीति तैयार कर सकता है। यह 2023 में भारतीय अध्यक्षता के लिए एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा। रणनीति चाहे जो भी हो, उसे निश्चित रूप से अपने मित्रों, प्रतिद्वंद्वियों और दुश्मनों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना चाहिए और एक ऐसी योजना विकसित करनी चाहिए जो सभी के लिए अनुकूल हो। (1)

भारत की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विकास नीतियों के माध्यम से दुनिया के आर्थिक विकास के पैमाने पर निरंतर उच्च स्तर पर होने के बावजूद, भारत अभी भी कई विकासात्मक समस्याओं से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है जो लगातार देश की समग्र प्रगति में बाधा उत्पन्न करती हैं। ब्रिटिश शासन से लेकर भारत की आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करते हुए, भारत ने इंच दर इंच तरक्की की है, अपनी धीमी लेकिन स्थिर प्रगति के लिए जवाबदेह कानूनों और नीतियों को लागू करते हुए, दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक की सूची में अपना स्थान बनाया है। हालाँकि, यह सब कुछ विकासात्मक समस्याओं से निपटने के लिए काफी नहीं है, जो विकसित देश की गड़ना में आने की भारत की महत्वकांशा को बाधित करता है।

आंकड़ों के अनुसार, 44.81 लाख पुरुष और इससे भी अधिक 52.89 लाख महिलाएं गरीबी रेखा के नीचे आती हैं। (2) भारत की वर्तमान जनसंख्या 1.41 अरब होने का अनुमान है। (3) भारत 2022 तक कोविड-19 के कारण देशव्यापी कुल मृत्यु दर में प्रथम स्थान पर है। (4) महामारी के कारण बढ़ने वाले व्यक्तिगत बोझ के अतिरिक्त, इसने अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2021 की अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई है। यह अब तक की सबसे बुरी गिरावट है, क्योंकि मंत्रालय ने 1996 में सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को तिमाही रूप से संकलित करना शुरू

किया था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा किए गए सर्वेक्षणों ने 2021 की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान बेरोजगारी दर में 7.9% से 12% की भारी वृद्धि दर्शायी है ।(5) इस आबादी के 6% से अधिक लोगों के पास सुरक्षित पानी की सुविधा नहीं है और भारत की लगभग 15% आबादी खुले में शौच करती है। घरेलू जल कनेक्शनों और शौचालयों की कमी जल जनित बीमारियों, बौनेपन और मृत्यु के लिए बड़े पैमाने पर योगदान करती है। (6)

सदी के मध्य तक, भारत में लगभग 3.5 करोड़ लोग वार्षिक तटीय बाढ़ का सामना कर सकते है, अगर उत्सर्जन ज्यादा होता है, तो शताब्दी के अंत तक 4.5 से 5 करोड़ लोगों के प्राणो को संकट है। जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट पर पारस्परिक सरकारी पैनल के अनुसार, भारत को जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक आर्थिक नुकसान हुआ है, वैश्विक स्तर पर उत्सर्जित होने वाले प्रत्येक टन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण देश को लगभग 86 डॉलर खर्च करना पड़ा है। दुनिया भर में 2021 में 36.4 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ। आर्थिक संकटो और प्रभावित वेतन से लेकर प्रभावित खाद्य उत्पादन तथा अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी तक, राष्ट्र विनाशकारी जलवायु परिवर्तन के परिणामों के एक व्यापक विस्तार को देख रहा है।(7)

भारत में निरक्षर लोगों की बहुत बड़ी संख्या पाई जाती है। भारत की कुल आबादी का 25% से अधिक अभी भी अशिक्षित है। (8) ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा दिए गए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में शामिल 180 देशों में से भारत 85वें स्थान पर है। (9) एनसीएसपीए का मानना है कि स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानों और दिशानिर्देशों के बावजूद, पूरे भारत में दलितों और आदिवासी समुदायों की सबसे ख़राब दशा है। यह समुदाय न केवल जाति व्यवस्था का शिकार है बल्कि संस्थागत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट से पता चलता है कि 2021 में अनुसूचित जातियों (एससी) के खिलाफ अत्याचार या अपराधों में 1.2% की वृद्धि हुई है। (10)

ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स (मानव विकास सूचकांक), 2022 में भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर है। (11) यह एक दुखद स्थिति का प्रमाण देता है, जो अभी भी भारत को घेरे हुए है और देश के वांछित विकास में एक बाधा है।

इसलिए, भारत के लिए समग्र विकास के मार्ग में आई दरारों को ठीक करने के लिए मजबूत नीतिगत उपाय करना अनिवार्य हो गया है। वर्ष 2023 में आगामी जी-20 अध्यक्षता, भारत को अपनी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने और इन मुद्दों के लिए व्यावहारिक समाधान प्रदान करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।

भारतीय प्रेसीडेंसी एजेंडा के प्रति समाज सेवी क्षेत्र का दृष्टिकोण

सिविल 20 जी-20 के संलग्न समूहों में से एक है। यह वैश्विक समाज सेवी क्षेत्र को उन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है जो मेजबान देश द्वारा निर्धारित जी-20 एजेंडे के साथ जुड़े होते हैं और एक समावेशी तथा सफल जी-20 प्रक्रिया के लिए जमीनी सुझाव प्रस्तुत करता हैं। जी-20 ने धीरे-धीरे समाज सेवी क्षेत्र के साथ जुड़ने और उन्हें पूरी प्रक्रिया में शामिल करने के महत्व को पहचाना है, और उन्हें नीतिगत बदलाव के लिए वैश्विक चर्चाओं में शामिल करने के लिए जगह बनाई है।

जी-20 प्रक्रिया में सी-20 को शामिल करना, निर्णय लेते समय अंतर्राष्ट्रीय कानून और उचित प्रथाओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करता है। इसलिए, समाज सेवी क्षेत्र 2023 में जी-20 द्वारा भारत को दिए गए अवसर को लेकर बेहद उत्साहित है। समाज सेवी क्षेत्र अनुसार प्रमुख सुझाव, भारतीय विकास के वर्तमान परिदृश्य की एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और उन अंतरो को उजागर करते हैं जिन पर तत्कालीन ध्यान देने और उनके समाधान की आवश्यकता है। एक विकासशील देश होने के नाते, भारत द्वारा अग्रणी नीतिगत पहल, दुनिया भर में कम प्रतिनिधित्व वाली और कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक नमूने / टेम्पलेट के रूप में जुड़ सकती है। भारत में समाज सेवी क्षेत्र, पहले से ही विकासात्मक बाधाओं को नियंत्रित करने की दिशा में व्यक्तिगत स्तर पर इन चिंताओं को उजागर कर चुका है। हालांकि, वर्ष 2023 में जी20 एजेंडे में इन्हे प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में शामिल करना बेहद महत्वपूर्ण होगा।

1. **सबके लिए स्वास्थ्य** - भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए है। 1947 में भारत के स्वास्थ्य परिदृश्य और 2022 के स्वास्थ्य परिदृश्य के बीच का अंतर स्पष्ट स्मरण कराता है कि एक विकासशील देश को कैसे उन्नति करनी चाहिए और किस प्रकार उभरना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी पहल शुरू करने से लेकर इतिहास की कुछ सबसे घातक बीमारियों पर काबू पाने तक, भारत ने वास्तव में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष किया है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में देश की कुछ सर्वाधिक उल्लेखनीय उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

   - भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था।
   - भारत ने मलेरिया की समस्या को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण सुधार किया है।

- भारत ने चेचक, कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया है।

  हालाँकि, अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई खामियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है और जी-20 एजेंडे के तहत इसे जरूर उठाया जाना चाहिए।

- आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 2021-2022 में स्वास्थ्य क्षेत्र में ही बजट आवंटन कम रहा है। 37,000 करोड़ के आवंटन के साथ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में पिछले वर्ष के खर्च की तुलना में 7% की वृद्धि हुई है। हालांकि, धीमी गति वाले शहरी स्वास्थ्य मिशन को बढ़ावा देने और पूरे देश में ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए अधिक आवंटन की आवश्यकता है। (12)

  नीतिगत सुझाव: इसलिए, प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना और प्रणालियों में निवेश करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

- सभी दीर्घकालीन लक्ष्यों में से एक, जो अन्य दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायता करता है, वह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) है। यह गरीबी, शिक्षा, भुखमरी, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल तक पहुंच, रोजगार और विकास, असमानता से निपटने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावो को कम करने पर दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों की प्रगति में सहायता करता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, यूएचसी को प्राप्त करने की प्रमुख रणनीतियों में से एक स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्तपोषण की पहल है। एक अध्ययन के अनुसार, भारत में वित्तीय संकट संरक्षण केवल 17.9 प्रतिशत था और चुनिंदा स्वास्थ्य स्थितियों के लिए रोकथाम और उपचार कवरेज 83.5 प्रतिशत था। (13)

  नीतिगत सुझाव: इसलिए, भारत को बढ़े हुए और नए वित्तीय संकट संरक्षण और स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

- एक और चुनौती, जिसका मुक़ाबला भारत स्वास्थ्य प्रणाली के संबंध में कर रहा है, जो महामारी के दौरान उजागर हुई थी, वह है डॉक्टरों, नर्सों, प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मियों और पैरामेडिकल प्रशिक्षित और कुशल चिकित्सा कर्मियों की कमी। भारत में 2019 में प्रत्येक 1000 रोगियों के लिए मात्र 0.9 चिकित्सक उपलब्ध थे। (14) डब्ल्यूएचओ 1,000 रोगियों पर 2.5 डॉक्टर की औसत का सुझाव प्रस्तुत करता है।

  नीतिगत सुझाव: इसलिए, भारत में बेहतर और सस्ती चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने में अधिक निवेश करना एक प्राथमिकता बनी हुई है।

2. सबके लिए आर्थिक सुरक्षा-

- मई 2022 तक, भारत में बेरोजगारी दर लगभग सात प्रतिशत दर्ज किया गया है, जो पिछले महीने की तुलना में कम है। अप्रैल 2020 में चरम पर पहुंचने के बाद से 2021 के दौरान बेरोज़गारी की दर में काफी गिरावट आई थी, लेकिन बार-बार होने वाले लॉकडाउन के साथ-साथ नए कोरोनोवायरस वेरिएंट के ब्रेकआउट के परिणामस्वरूप देश में बेरोज़गारी की प्रवृत्ति में कमी आई है। (15) परिणामस्वरूप, सभी के लिए अच्छी नौकरी की सुविधा और सभी भारतीयों के लिए न्यूनतम मौलिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

- हाल के वर्षों में भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र आत्मनिर्भरता रहा है। देश में रोजगार सृजन सुनिश्चित करते हुए इसकी प्राप्ति की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में उद्यमिता और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना है। यह दीर्घकालीन उपयुक्त विकास, समृद्धि और कल्याण को भी सुगम बनाएगा जो शेष विश्व के लिए सुधार के मार्ग के रूप में कार्य कर सकता है और सामूहिक रूप से उनके हितों को भी पूरा कर सकता है। इसलिए, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर बहुक्षेत्रीय सहयोग समय की आवश्यकता है।

  नीतिगत सुझाव: कारोबारी माहौल में सुधार, कम नियमन, कर कटौती और भौतिक तथा मानव संरचना में निवेश को बढ़ाना ऐसे कारक हैं जो उद्यमशीलता को आगे बढ़ा सकते हैं।

3. सभी के लिए उत्तम शिक्षा - कोविड-19 का स्कूली शिक्षा पर प्रभाव अभूतपूर्व अनुभव रहा है। इसने राज्यों, वर्ग, जाति, लिंग और क्षेत्र में बड़ी संख्या में बच्चों को प्रभावित किया है। स्कूलों को बंद करने और पारंपरिक कक्षाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने के फैसले से न केवल बच्चों में सीखने की असमानता बढ़ रही है, बल्कि डिजिटल उपकरणों / डिवाइड के कारण बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल से बाहर हो रहे हैं। सभी के लिए समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान स्थिति के साथ-साथ महामारी के अतिरिक्त बजट बहुत महत्वपूर्ण है।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, सभी के लिए उत्तम शिक्षा को सुलभ बनाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत एक नीति दस्तावेज है, जिसने भारत के सकल घरेलू उत्पाद के न्यूनतम 6 प्रतिशत तक शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट प्रावधान में वृद्धि की आवश्यकता को दोहराया है। हालांकि, 2021-22 में शिक्षा के लिए बजट आवंटन केंद्र सरकार और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से खर्च, देश के सकल घरेलू उत्पाद के

3.1 प्रतिशत से बहुत कम था। 6 प्रतिशत के लक्ष्य और उसमे निवेश की वास्तविक स्थिति के बीच एक बड़ा अंतर कई दशकों से बना हुआ है। (16)

- अगस्त 2021 में, समग्र शिक्षा अभियान (एसएमएसए) को वित्त वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाले 2,94,283 करोड़ के कुल बजट के साथ अगले पांच वर्षों के लिए हरी झंडी मिली। यह विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल मीडिया के माध्यम से पूर्ण शिक्षा पर जोर देने के साथ योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़ा है। भारत सरकार ने योजना के लिए 37,383 करोड़ का अनुमानित बजट (बीई) आवंटित किया - इसमें पिछले वर्ष के बीई से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और यह संशोधित अनुमान / रिवाइज्ड एस्टीमेट (आरई) से 25 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, पिछले दो वर्षों में अधिकांश राज्यों के लिए स्वीकृत धन की मात्रा में कमी देखी गई है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के एक अध्ययन में विश्लेषण किए गए, जिसमे 19 राज्यों में से सत्रह राज्यों ने वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के बीच बजट में कमी देखी। वित्त वर्ष 2021-22 में 14 राज्यों के बजट में और गिरावट आई। (17) भारत में डिजिटल शिक्षा, शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन महामारी के समय इसकी वास्तविक क्षमता सामने आई, जब स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे और कक्षाएं ऑनलाइन हो गई थी। छात्रों के पास शिक्षा प्राप्त करने का एकमात्र विकल्प यही बचा था।

परिणामस्वरूप, शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी तक समान पहुंच प्रदान करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा, सभी स्तरों पर उत्तम शिक्षा के वित्तपोषण में वृद्धि भी अनिवार्य हो गई।

नीतिगत सुझाव: महामारी के कारण देश में स्कूली बच्चों की पहचान करने के लिए बजट हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। एसएमएसए के तहत स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए बजट को अगले कुछ वर्षों तक बढ़ाने की जरूरत है, ताकि शिक्षा के नुकसान को दूर किया जा सके, जिसका उन्होंने अनुभव किया है।

-योजना के अंतर्गत संसाधनों की मौजूदा कमी की भरपाई के लिए योजना के लिए आवंटित कुल बजट में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता है।

4. दीर्घकालीन साधनों के माध्यम से संरचना विकास-

यदि भारत भविष्य में विकसित राष्ट्रों में से एक बनने की इच्छा रखता है, तो उसे लचीले और स्थायी संरचना निर्माण के माध्यम से एक जलवायु-प्रतिरोधक अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देनी चाहिए।

मानव प्रेरित जलवायु- जलवायु परिवर्तन दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। 2021 में, भारत में कुल आबादी का लगभग एक तिहाई शहरों में रहता था। इस प्रवृत्ति में पिछले दशक में शहरीकरण में लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका अर्थ यह है कि लोग काम खोजने और शहरों में रहने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से दूर चले गए हैं। (18) विश्व शहरीकरण संभावना (1996 संशोधन) के अनुसार, वर्ष 2025 में शहरी आबादी बढ़कर 42.5 प्रतिशत (566 मिलियन) हो जाएगी। (19)

अत्यधिक मौसम परिवर्तन, भूकंप, सूखा, चक्रवात, जंगल की आग, बाढ़ आदि पर्यावरणीय आपदाओं के प्रकरण में गंभीर वृद्धि, जलवायु परिवर्तन का परिणाम है, जो आश्चर्यजनक गति से हो रहा है। (20) यह सब जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग के परिणामस्वरूप जीएचजी उत्सर्जन में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण हो रहा है। जीएचजी उत्सर्जन से निपटने और उन्हें उस स्तर तक सीमित करने के लिए जहां जलवायु परिवर्तन को बदला जा सके, मौजूदा संरचना को लचीला और स्थायी बनाने की जरूरत है।

नीतिगत सुझाव: इसलिए, भारतीय अध्यक्षता के दौरान जी-20 एजेंडे में हरित संरचना में निवेश एक प्राथमिकता होनी चाहिए।

5. जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं को संबोधित करना-

1901 से 2020 तक वैश्विक तापमान में लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन का अर्थ समुद्र के स्तर में वृद्धि, अपेक्षित मौसम की स्थिति में बदलाव, और भी बहुत कुछ है। (21) मानव की बुनियादी ज़रूरतें, पानी, भोजन, ऊर्जा जलवायु परिवर्तन के कारण पारिस्थितिक तंत्र, वन्य जीवन, में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आईपीसीसी रिपोर्ट, 2022 के अनुसार, "मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन प्रकृति में खतरनाक और व्यापक व्यवधान पैदा कर रहा है और इन संकटों को कम करने के प्रयासों के बावजूद भी यह अरबों लोगों के जीवन और आजीविका को प्रभावित कर रहा है।" (22)

नीतिगत सुझाव: भारत को कुल जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए नीतिगत उपायों पर ध्यान देना चाहिए।

- स्थायी एवं दीर्घकालीन जीवाश्म ईंधन विकल्पों की तलाश के लिए निवेश किया जाना चाहिए।
- कार्बन उत्सर्जन को महत्वपूर्ण अंतर से कम करने पर ध्यान दें और देश को कार्बन न्यूट्रल (virakt) बनाएं।
- भारतीय अध्यक्षता को आपदा की तैयारी और आपदा के बाद की स्थितियों के प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए बढ़ावा देना चाहिए।

6. भ्रष्टाचार विरोधी उपाय-

- कोविड-19 के प्रभाव से उभरने के साथ भ्रष्ट प्रथाओं के खिलाफ मजबूत रुख बनाए रखना महत्वपूर्ण है। पारंपरिक भ्रष्टाचार विरोधी नीतियां महामारी जैसी अभूतपूर्व स्थिति में प्रभावी साबित हुई हैं। भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों को ऐसे समय में भी सार्थक बने रहने के लिए लचीला और समग्र होना चाहिए।

  नीतिगत सुझाव: इनकी प्रणालियों और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए तंत्र को निरिक्षण की आवश्यकता है।

  - सरकारी प्रणालियाँ उपभोक्ता के अनुकूल, पारदर्शी, मुक्त प्रवाह और नियमित रूप से अपडेट तथा, नागरिक-केंद्रित होनी चाहिए।
  - राज्य और केंद्र सरकारों को निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत, समाज सेवी क्षेत्र और मीडिया सहित विभिन्न हितधारकों को सुशासन को बढ़ावा देने और उसका अभ्यास करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
  - भ्रष्टाचार के मामलों में कमी सुनिश्चित करने के लिए भारत के प्रशासन के दृष्टिकोण को विकेंद्रीकृत करना सहायक हो सकता है, खासकर महामारी के समय में। निर्णय लेने के लिए स्थानीय अधिकारियों को अधिकार सौंपने से एकाधिकार की समाप्ति और बेहतर जन-केंद्रित निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

7. लिंग अंतराल को कम करना-

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 की जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लिंग अंतराल 62.5% तक बढ़ गया है। हम कुछ हद तक इस गिरावट के लिए महामारी को जिम्मेदार ठहरा सकते है। यह राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व, श्रम बल की भागीदारी दर में कमी, महिलाओं के लिए खराब स्वास्थ्य सुविधाओं, असमान मजदूरी, पुरुष से महिला साक्षरता अनुपात में व्यापक अंतर और बहुत से अन्य कारण है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2021 में भारत दुनिया भर के 156 देशों में से 140वें स्थान पर आया है। आंकड़ों ने यह भी दर्शाया कि भारत ने केवल 9.1% के साथ राजनीतिक सशक्तिकरण में सबसे खराब प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य आयाम के संबंध में, भारत 2021 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशो में से एक था। 2020 से लिंग वेतन अंतर भी 3% बढ़ गया। (23)

- इन सभी क्षेत्रों में लैंगिक अंतर को कम करने के लिए भारत ने सक्रिय रूप से कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन मौजूदा योजनाओं के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यदि आवश्यक हो, तो संशोधन द्वारा निर्मित प्रभाव का नियमित निरिक्षण किया जाये ।
- नेतृत्व क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत में शिक्षा प्रणाली और कार्यस्थलों में मुख्यधारा लैंगिक दृष्टिकोण में सुधार लाना होगा ।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करें और उन व्यवसायों को मान्यता दें जो एक पारिस्थितिक तंत्र विकसित करते हैं जहां महिला उद्यमी फल-फूल सकती हैं।
- महिला-केंद्रित नीतियों में कार्य पुनः आरम्भ, काम के घंटो में लचीलापन, मासिक धर्म की छुट्टी, समान वेतन, हाइब्रिड वर्किंग मॉडल आदि शामिल हो सकते हैं।

8. सीएसओ के लिए एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देना

भारत में समाज सेवी क्षेत्र अपनी जीवंतता, नवीनता और साक्ष्य-आधारित पक्ष के लिए विख्यात है। स्वतंत्रता के बाद से, समाज सेवी क्षेत्र ने भारत और राष्ट्र-निर्माण में विकासात्मक समस्याओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने देश के उन दूरस्थ हिस्सों में सरकारी कार्यो का सहयोग किया है, जहां सरकार की सीमित पहुंच थी। भारत में सीएसओ न

केवल सरकार की नीतियों और सेवाओं में अंतर को कम करते हैं, बल्कि देश के समग्र सकल घरेलू उत्पाद में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह क्षेत्र लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है और दिन-प्रतिदिन तेजी से विस्तार कर रहा है। हालाँकि, इस क्षेत्र का सटीक विस्तार आज तक सही ढंग से मापा नहीं गया है।

सरकार की भूमिका समाज सेवी क्षेत्र को नियमित करने की है, उसे प्रतिबंधित करने की नहीं है। एमएचए के अनुसार, जिन संगठनों की विदेशी फंडिंग रद्द कर दी गई है, उनकी संपत्ति संबंधित राज्य सरकार के प्रधान सचिव को दे दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, विदेशी वित्त पोषित सीएसओ के कार्यों के निरिक्षण के लिए ऑनलाइन तंत्र विकसित किया गया है। अफसोस की बात यह है कि कई संगठनों पर कड़ी नजर रखी गई, उनके एफसीआरए लाइसेंस निलंबित कर दिए गए और उनके परिसरों में छापेमारी की गई।

जबकि यह सब नियंत्रण, उत्पीड़न और अविश्वास के बराबर है, जो कि सरकार को नहीं करना चाहिए, उन्हें बेहतर समाज की दिशा में काम करने और भारत के नागरिकों को बेहतर जीवन यापन स्थिति प्रदान करने के लिए समाज सेवी क्षेत्र का सहयोग करना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कोविड-19 के दौरान किया था, और सीएसओ के कार्य करने के लिए एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देने में सहयोग करना चाहिए । अंत में, दोनों क्षेत्रों का राष्ट्र निर्माण का एक समान लक्ष्य है।

कॉर्पोरेट कानूनों को सरल बनाने के लिए सुधार किए गए हैं, "व्यापार में आसानी" को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता को अत्यधिक सहयोगी और प्रोत्साहित बनाया गया है, लेकिन समाज सेवी क्षेत्र ने इन्हे विनियमित करने वाले कानूनों में ऐसा कोई सरलीकरण नहीं देखा है। बिजनेस स्टार्ट-अप्स को कई प्रकार का सहयोग मिलता है, लेकिन नए सीएसओ को नियामक तंत्र के अंतर्गत शुरुआत में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है।(24)

इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानून, उदाहरण के लिए सीएसओ के पंजीकरण के लिए, पुराने हो गए हैं। युगों से इनमें संशोधन नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, उनमें स्पष्टता की कमी है, भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न सीएसओ के लिए अलग-अलग नियामक अनुपालन हैं, और इसलिए, भारत में समाज सेवी क्षेत्र के प्रशासन के लिए एकरूपता और निर्धारित मानकों की कमी है।

इसलिए, जी-20 को समाज सेवी क्षेत्र के लिए सक्षम वातावरण बनाने के लिए नीतिगत परिवर्तनों पर ध्यान देना चाहिए। भारत में पंजीकरण कानूनों को सुव्यवस्थित करना, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, विकास संगठनों, विशेषज्ञ समूह, धार्मिक निकायों और इसी तरह के संस्थानों में स्पष्ट अंतर करना एक आवश्यकता है। एफसीआरए संबंधी शिकायतों को देखने के लिए एक उच्च प्राधिकरण के गठन पर विचार किया जाना चाहिए। आपसी सम्मान और साझा दृष्टि के आधार पर सरकार और समाज सेवी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तंत्र तैयार करना चाहिए।

निष्कर्ष

जी-20 शिखर सम्मेलन के पिछले अनुभवों से सीखते हुए, भारतीय समाज सेवी क्षेत्र को भारत सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, कि वे इन मुद्दों पर काम करेंगे और अगले वर्ष के लिए जी-20 एजेंडा तैयार करते हुए उन्हें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध करेंगे। यह भी माना जा रहा है कि सरकार समाज सेवी क्षेत्र के सहयोग से काम करती है और वह उसे अपनी अध्यक्षता के सफल होने के लिए प्रतिबंधात्मक होने के बजाय निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करे। उन्हें अपने सामान्य एजेंडे पर काम करने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र, समाज सेवी क्षेत्र और अन्य के साथ भागीदारी करते हुए एक संतुलन सुनिश्चित करना चाहिए। उपर्युक्त प्रमुख बिंदु उन सभी चुनौतियों पर आधारित हैं जो भारत के एक विकसित राष्ट्र बनने के रास्ते में आती हैं और इन्हें आगामी जी-20 अध्यक्षता के लिए तैयार किया जाना चाहिए। भारतीय समाज सेवी क्षेत्र के पास जमीनां अनुभवों और उदाहरणों का एक विश्वकोश है, जो आगामी नीति निर्माण को प्रभावित कर सकता है। भारत, एक लोकतांत्रिक देश है, तथा पिछले कुछ वर्षों में एक विकसित राष्ट्र में हस्तांतरण करने के अपने प्रयासों में अत्यधिक सफल रहा है ! समाज सेवी क्षेत्र यह आशा करता है, कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों को सम्मिलित किया जाएगा और उन पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा। भारतीय समाज सेवी क्षेत्र एक रचनात्मक जी-20 अध्यक्षता की आशा करता है और जो भारत के नागरिकों के हितो में अधिकतम परिणामो की अपेक्षा करता है।

संदर्भ

1. https://www.gatewayhouse.in/geopolitics-g20-and-indias-choices/
2. https://www.statista.com/statistics/1270990/india-total-population-living-in-poverty/
3. https://www.weforum.org/agenda/2022/08/world-population-countries-india-china-2030/
4. https://ourworldindata.org/coronavirus
5. https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/shreyansh-mangla/impact-of-covid-19-on-indian-economy-2-35042/
6. https://water.org/our-impact/where-we-work/india/
7. https://weather.com/en-IN/india/climate-change/news/2022-03-01-ipcc-report-2022-predictions-for-india
8. https://timesofindia.indiatimes.com/india/75-years-75-literacy-indias-long-fight-against-illiteracy/articleshow/93555770.cms
9. https://www.transparency.org/en/cpi/2021
10. https://www.newsclick.in/NCRB-Report-Shows-Rise-Atrocities-Towards-Dalits-Adivasis
11. https://www.undp.org/india/press-releases/india-ranks-132-human-development-index-global-development-stalls
12. https://www.financialexpress.com/budget/budget-lacks-push-for-primary-healthcare-2423447/
13. https://oce.ovid.com/article/01714638-201709000-00020
14. https://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.PHYS.ZS?locations=IN&most_recent_value_desc=true
15. https://www.statista.com/statistics/1111487/coronavirus-impact-on-unemployment-rate/
16. https://accountabilityindia.in/blog/india-has-been-unable-to-boost-public-education-spending-to-6-percent-of-gdp/#:~:text=However%2C%20in%202021%2D22%2C,remained%20for%20many%20decades%20now.
17. https://cprindia.org/wp-content/uploads/2022/06/Samagra-Shiksha_2022-23.pdf
18. https://iirfranking.com/blog/knowledge-source/digital-india-empowers-digital-education/
19. https://www.statista.com/statistics/271312/urbanization-in-india/
20. https://niti.gov.in/planningcommission.gov.in/docs/reports/sereport/ser/vision2025/urban.pdf
21. https://www.cseindia.org/climate-india-2022-11463
22. https://www.noaa.gov/education/resource-collections/climate/climate-change-impacts
23. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
24. https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf
25. https://www.icnl.org/wp-content/uploads/Legal-Framework-for-Civil-Society-in-India-Dadrawala-vf.pdf

HEINRICH BÖLL STIFTUNG
INDIA

www.boell.de, www.in.boell.org

हेनरिक बॉल स्टिफतुंग के बारे में

हेनरिक बॉल स्टिफतुंग एक जर्मन संगठन और हरित आंदोलन का हिस्सा है जो दुनिया भर में समाजवाद, उदारवाद और रूढ़िवाद की पारंपरिक राजनीति की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ है। हम एक ग्रीन थिंक–टैंक और एक अंतरराष्ट्रीय नीति नेटवर्क हैं, हमारे मुख्य सिद्धांत पारिस्थितिकी और स्थिरता, लो. कतंत्र और मानवाधिकार, आत्मनिर्णय और न्याय हैं। हम लैंगिक लोकतंत्र पर विशेष जोर देते हैं, जिसका अर्थ है सामाजिक मुक्ति और महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकार। हम सांस्कृतिक और जातीय अल्पसंख्यकों के समान अधिकारों के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। अंत में, हम अहिंसा और सक्रिय शांति नीतियों को बढ़ावा देते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, हम उन अन्य लोगों के साथ रणनीतिक साझेदारी चाहते हैं जो हमारे मूल्यों को साझा करते हैं। हमारे उपनाम, हेनरिक बॉल, उन मूल्यों को व्यक्त करते हैं जिनके लिए हम खड़े हैं: स्वतंत्रता की सुरक्षा, नागरिक साहस, सहिष्णुता, खुली बहस, और विचार और कार्रवाई के स्वतंत्र क्षेत्रों के रूप में कला और संस्कृति का मूल्यांकन। हमारा भारत संपर्क कार्यालय 2002 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था।

VANI
Celebrating 30 Years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

www.vaniindia.org

वाणी के बारे में

एक मंच के रूप में, वाणी स्वैच्छिकवाद को बढ़ावा देती है और स्वैच्छिक कार्रवाई के लिए जगह बनाती है। एक नेटवर्क के रूप में, यह देश में स्वैच्छिक कार्रवाई के वास्तविक राष्ट्रीय एजेंडे के निर्माण के लिए सामान्य क्षेत्रीय मुद्दों और चिंताओं के अभिसरण को लाने का प्रयास करता है। यह स्वैच्छिक क्षेत्र के विभिन्न प्रयासों और पहलों के लिंकेज को भी सुगम बनाता है।

अस्वीकरण: यह प्रकाशन हेनरिक बॉल स्टिफटंग के सहयोग से तैयार किया गया था। प्रकाशन में निहित विचार और विश्लेषण लेखक(कों) के हैं और जरूरी नहीं कि वे फाउंडेशन के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।